कंवलजीत सिंह अहलूवालिया के समक्ष।

हरि सिंह, -प्रार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1995 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7686

28 जुलाई, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब पुलिस नियम, 1934-धारा 16.2 और 16.38 (1)-ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाया गया कांस्टेबल - कदाचार - सेवा से बर्खास्तगी - याचिकाकर्ता द्वारा 33 साल से अधिक की सेवा प्रदान करना - याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कदाचार की कोई पिछली घटना नहीं - याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त और उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की लंबाई को ध्यान में रखते हुए दंडित प्राधिकारी - सेवा से बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदलने का आदेश दिया गया और याचिकाकर्ता को इससे होने वाले सभी परिणामी लाभों का हकदार माना गया।

माना जाता है कि बर्खास्तगी के आदेश ने याचिकाकर्ता के पिछले आचरण पर विचार नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने सजा सुनाए जाने की तारीख को 33 साल की निर्बाध सेवा प्रदान की थी। यह उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का पहला उदाहरण था। सजा देने वाले प्राधिकारी ने न तो याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त और न ही उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की लंबाई और इस तथ्य पर विचार किया कि वह अपनी पेंशन से वंचित हो जाएगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से कदाचार को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि यदि सेवा से बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया जाता है, तो यह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

(पैरा 5)

धीरज चावला, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए।*

हिमांशु राज, ए.ए.जी., हरियाणा, *उत्तरदाताओं के लिए।*

कवलजीत सिंह अहलूवालिया, जे.

(1) याचिकाकर्ता को 26 फरवरी, 1962 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था और 33 साल से अधिक की सेवा का श्रेय उसे दिया गया था, जब कदाचार के आधार पर, उसे 21 अगस्त, 1992 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने 21 अगस्त के आदेश को रद्द करने की मांग की है। 1992 पुलिस अधीक्षक, हिसार द्वारा पारित अनुलग्नक पीएल, जिसके तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपील की थी और- दिनांक 18 मार्च, 1993 के आदेश *के तहत*, अनुलग्नक पी 2। पुलिस उप महानिरीक्षक, हिसार रेंज। हिसार ने याचिकाकर्ता को दी गई बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एक आरसीवीज़-कम-एमसीसी याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया - अनुबंध पी 3 के आदेश *के अनुसार*, याचिकाकर्ता ने अनुबंध पी 2 और पी 3 में आदेशों को रद्द करने की भी मांग की।

(2) संक्षिप्त तथ्य 21 अगस्त, 1992 के आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी 1 से एकत्र किए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी, क्योंकि वह 2 मार्च, 1992 को फतेहाबाद के पुलिस उपाधीक्षक के निवास पर गार्ड ड्यूटी के दौरान एसआई सुखदेव सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी सिटी फतेहाबाद द्वारा की गई जांच के दौरान शराब के नशे में पाया गया था। याचिकाकर्ता की कानूनी जांच भी जनरल अस्पताल, फतेहाबाद में की गई। श्री राम गोबी, पुलिस उपाधीक्षक, टोहाना ने जांच की और एचसी बाल वंत सिंह, सी भूप सिंह, मगर राम के बयान दर्ज किए। पुलिस उपाधीक्षक फतेहाबाद के एचसी जगदीश चंदर, डॉ. ए.के. चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल, फतेहाबाद और एसआई सुखदेव सिंह। याचिकाकर्ता के कहने पर इन गवाहों से जिरह की गई। दंड प्राधिकारी के समक्ष, एक दलील उठाई गई थी कि वर्तमान मामले में, नियम 16.3 8 (पंजाब पुलिस नियमों (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के 1) के अनुसार, इसलिए, याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस दलील

को सजा देने वाले प्राधिकारी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि सार्वजनिक व्यवहार के संबंध में कदाचार शामिल नहीं था, तो जिला मजिस्ट्रेट की सहमति आवश्यक नहीं थी। सजा देने वाले प्राधिकरण ने इस परिस्थिति को ध्यान में रखा कि डॉक्टर की राय के अनुसार, याचिकाकर्ता शराब के नशे में था और उसने रक्त और मूत्र के नमूने देने से इनकार कर दिया था। यह अनुमान लगाया गया था कि वर्दी में ड्यूटी के दौरान, याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था, इस प्रकार, वही कदाचार था और सख्त कार्रवाई के लिएउत्तरदायी था

तदनुसार, याचिकाकर्ता को सेंडी से बर्खास्त कर दिया गया था। जैसा कि पहले कहा गया है, अपील और पुनरीक्षण-सह-दया याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील धीरज चावला ने तर्क दिया है कि 'कदाचार का सबसे गंभीर कृत्य' शब्द का उपयोग करके, याचिकाकर्ता को 33 साल की सेवा के फल से वंचित कर दिया गया है और इस प्रकार, दी गई सजा बहुत कठोर है और याचिकाकर्ता को जिम्मेदार कदाचार के अनुरूप नहीं है। **हरजीत सिंह और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य (1)** पर भरोसा किया गया है, जिसमें नियमों के नियम 16.2 पर ध्यान दिया गया था कि बर्खास्तगी केवल कदाचार के गंभीर कृत्यों के लिए दी जानी चाहिए या निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में असुधार्यता और पुलिस सेवा के लिए पूर्ण अयोग्यता साबित होती है। इस तरह के एक पुरस्कार बनाने में, अपराधी की सेवा की लंबाई और पेंशन के लिए उसके दावे के लिए किया जाएगा. इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की ओर से एकान्त कार्य ऐसा था कि वह पुलिस भेजने के लिए असुधार्य और अप्रकाशित हो गया था। रिकॉर्ड पर कोई पिछली घटना साबित नहीं हुई है जब याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार किया हो। इसलिए, धारा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए केवल उसके शब्दों का उपयोग करना आवश्यक है, न्याय का हित नहीं। संक्षेप में यह **हरजीत सिंह की सहजता** *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून की उक्ति है। इसलिए, **हरजीत सिंह (** सुप्रा) मामले में **सर्वोच्च** न्यायालय ने निर्णय दिया कि रात्रि 900 बजे से मध्याह्न पश्चात् 200 बजे तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए अपराधी कांस्टेबल को सेन्डी से बर्खास्त करने के बजाय अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, **पंजाब राज्य बनाम धर्म सिंह, (2)** में 11 माह की अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सजा को सेवा से बर्खास्तगी से अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवतत कर दिया गया। **एसआई सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और** अन्य, (3) में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने माना है कि आमतौर पर, न्यायालय नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दी गई सजा की मात्रा में बदलाव नहीं करेगा, जब तक कि यह कदाचार या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन न पाया जाए। **जानबूझकर अनुपस्थिति के लिए एसआई सुरिंदर सिंह के मामले** *(सुप्रा)* में, अपराधी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी की सजा को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदल दिया गया था।

(1) 2007 (9) एस.सी.सी. 582
(2) 1997 (2) एससीसी 550
(3) 2008 (4) एस.सी.टी. 72

उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एसआई सुरिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में, डिवीजन बेंच ने पंजाब राज्य बनाम
राम सिंह (4) पर भरोसा किया था, उसी का पैरा 8 इस प्रकार है:--

"8. नियमों का नियम 16.2 पंजाब राज्य बनाम राम सिंह, 1992(3) एससीटी 448: (1992) 4 एससीसी 54 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के लिए आया। नियम की व्याख्या करते समय, माननीय 'ब्लू सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित शब्दों में कानून का हवाला दिया:
"7. नियम 16.2(1) में दो भाग हैं। पहला भाग कदाचार के गंभीरतम कृत्यों के संदर्भ में है जिसमें बर्खास्तगी का
आदेश देना शामिल है। निस्संदेह गंभीरतम कदाचार और गंभीर कदाचार के बीच अंतर है। बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले इसे यह अनिवार्य होना चाहिए कि बर्खास्तगी आदेश केवल तभी दिया जाना चाहिए जब कदाचार के गंभीरतम कृत्य हों। वह भी तब जब यह लंबी सेवा अवधि के बाद अपराधी के पेंशन अधिकारों को बाधित करता है। जैसा कि कहा गया है कि पहला भाग कदाचार के गंभीरतम कृत्यों से संबंधित है। सामान्य धाराओं के तहत अधिनियम एकवचन में बहुवचन शामिल है, अधिनियम में कार्य शामिल हैं। यह तर्क कि बर्खास्तगी का पुरस्कार देने के लिए कदाचार के कृत्यों की
बहुलता होनी चाहिए, विचित्र है। शब्द "कार्य" में एकवचन "कार्य" भी शामिल होगा। यह उन कृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं है जिनकी शिकायत की गई है लेकिन इसकी गुणवत्ता, घातक प्रभाव और अपमानजनक कृत्य से उत्पन्न होने वाली स्थिति की गंभीरता'। सबसे गंभीर कृत्य का रंग आसपास या उपस्थित परिस्थितियों से पता लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उस अपराधी को लीजिए जिसने 29 साल की लगातार सेवा की और उसका रिकॉर्ड बेदाग रहा, 30वें साल में वह सार्वजनिक धन का गबन करता है या हेराफेरी को छुपाने के लिए झूठे रिकॉर्ड बनाता है। lle केवल एक बार प्रतिबद्ध
है. क्या इसका मतलब यह है कि उसे बर्खास्तगी की सजा नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उस वर्ष तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह अपना पूर *पेंशन* प्राप्त कर सके

(4) (1992) 4 एस.सी.सी. 54

जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। इसलिए, भ्रष्टाचार का एक ही कार्य नियम के तहत बर्खास्तगी के आदेश को कदाचार के सबसे गंभीर कार्य के रूप में देने के लिए पर्याप्त है।

8. नियम का दूसरा भाग निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव को दर्शाता है जो पुलिस सेवा की असुधार्यता और पूर्ण अयोग्यता साबित करता है और अपराधी की सेवा की अवधि और, पेंशन के लिए उसके दावे को एक उपयुक्त मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए। 'यह तर्क कि दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, हमें अतार्किक प्रतीत होता है। दूसरा भाग चरित्र में नाबालिग के कदाचार के लिए संदर्भित है जो अपने आप में बर्खास्तगी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कदाचार के निरंतर कार्य के कारण सेवा मनोबल पर कपटी संचयी प्रभाव होगा, सुधार का अवसर देने के लिए उदार दृष्टिकोण लेने का आधार हो सकता है। ऐसे अवसर प्रदान करने के बावजूद यदि अपराधी अधिकारी सुधरने योग्य साबित नहीं होता है और सेवा में अनुशासन बनाए रखने की तुलना में सेवा में बने रहने के लिए पूरी तरह से अयोग्य पाया जाता है, तो अपराधी अधिकारी को बर्खास्त करने के बजाय, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदावनति की कम सजा या निचले ग्रेड या रैंक में पदावनति या उसके भविष्य के रोजगार की संभावनाओं को प्रभावित किए बिना सेवा से हटा दिया जाता है, यदि कोई न्याय के सिरों को पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए अपराधी अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी से आदतन अनुपस्थित रहता है। खुद को सुधारने का मौका देने के बावजूद वह ड्यूटी से बार-बार अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने खुद को असुधार्य साबित किया और इस तरह सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य साबित किया। इसलिए, उसकी लंबी सेवा अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे को ध्यान में रखते हुए, उसे अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है ताकि वह आनुपातिक पेंशन अर्जित कर सके। 'नियम का दूसरा भाग उस क्षेत्र में संचालित होता है। यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि गंभीर कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्तगी का आदेश सभी पेंशन लाभों को जब्त कर सकता है। इसलिए, शब्द 'या' को

"और" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह उसे विघटनकारी और स्वतंत्र होना चाहिए। दोनों खंडों को जोड़ने वाली सामान्य कड़ी "कदाचार का सबसे गंभीर कार्य / इसी प्रकार का विचार इस कोंटी की एक अन्य खंडपीठ द्वारा **धन सिंह** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य, (5) के मामले में दोहराया गया था। धरणी पाल** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य, (6) में,** इस न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि जहां दोषी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई 37 साल की सेवा को दंड प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, सजा आदेश तर्कहीन लगेगा। **पंजाब राज्य और अन्य** *बनाम* **पियारा सिंह में,** (7) याचिकाकर्ता की तरह अपराधी कर्मचारी ड्यूटी पर नशे में पाया गया था। मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चूंकि उसके द्वारा प्रदान की गई 22 साल की सेवा पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए सेवा से बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया गया था।

(4) राज्य के वकील ने **पूर्व कांस्टेबल राम कृष्ण** *बनाम* **हरियाणा राज्य, (8)** पर भरोसा किया है कि यदि पुलिस के सदस्य विधिवत शराब का सेवन करते हैं और विधिवत अनुपस्थित रहते हैं, तो यह कदाचार है। लेकिन फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें अपराधी कर्मचारी का कदाचार का एक सिद्ध रिकॉर्ड था।

(5) मैंने बर्खास्तगी के आदेश का अवलोकन किया है। इसने याचिकाकर्ता के पिछले आचरण पर विचार नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने सजा सुनाए जाने की तारीख को 33 साल की निर्बाध सेवा प्रदान की थी। यह उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का पहला उदाहरण था। सजा देने वाले प्राधिकारी ने न तो याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त और न ही उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की लंबाई और इस तथ्य पर विचार किया कि वह अपनी पेंशन से वंचित हो जाएगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से कदाचार को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया जाता है, यह हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

(6) इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया जाता है, मैं इससे होने वाले सभी परिणामी लाभों के लिए हकदार होगा। मैं कम हो गया। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

R.N.R.

---

(5) 2008(3)SCT816'

(6) 2009(4) SCT 130

(7) 2004(2) RSJ 279

(8) 1998 (1) SCT 561

अस्वीकरण :स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिकउद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्तर हेगा ।

प्रिंस कुमार

प्रशिक्षुन्यायिकअधिकारी

कैथल ,हरियाणा